

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवामें,

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून:दिनांक: 15 जून, 2010

विषय:-छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में संस्कृत शिक्षा विभाग के शैक्षणिक पदों के दिनांक 01-01-2006 से स्वीकृत प्रतिस्थापित वेतनमान (रिप्लेसमेंट स्केल) का उच्चीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति क्रमशः शासनादेश संख्या-395/XXVII (7) /2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 एवं शासनादेश संख्या-25/XXVII (7) /2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 के द्वारा की गयी है।

2- वेतन समिति (2008) ने अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के शिक्षकों की भांति राज्य सरकार के शिक्षकों को भी उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1-4-2009 से स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की है। वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय/अशासकीय सहायता शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के लिए उन शैक्षणिक पदों के लिये जिनके वेतनमान विद्यालयी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों के समतुल्य वेतनमान में है, शासनादेश सं० 20/सं०शि०/XXIV-4/2008 दिनांक 23 जनवरी 2008 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 118/सं०शि०/XXIV-4/2008 दिनांक 15 जुलाई 2008 के अनुक्रम में शिक्षकों के साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान को केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान क्रमशः ग्रेड-3, ग्रेड-2 एवं ग्रेड-1 के श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए संलग्नक-1 की तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान वेतनमान के स्थान पर कालम-4 में उल्लिखित वेतनमान के सादृश्य कालम-5 एवं 6 में क्रमशः उल्लिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01-01-2006 से प्राकल्पित आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्चीकृत करते हुये वास्तविक लाभ दिनांक 1-4-2009 से दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

↓(1) नियमित रूप से एक निश्चित समय अन्तराल में शिक्षकों की दक्षता एवं कार्यकुशलता का आंकलन किया जाना चाहिए तथा उच्चतर वेतनमान देते समय आंकलन के परिणामों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। ऐसी किसी संस्था से जो इस विषय में दक्षता रखती हो, प्रशिक्षण



एवं क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम तैयार कराने चाहिए एवं कार्यकुशलता के आंकलन हेतु मानक निर्धारित किये जाने चाहिए। Achievement व Output समस्या नहीं है अतः Incentive/Disincentive के मानक निर्धारित किये जायें।

↓(2) शासकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के गत तीन वर्षों के दसवीं व बारवी कक्षा के बोर्ड परीक्षा के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन कर राज्य के राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों की ग्रेडिंग की जायें तथा सम्बन्धित शिक्षकों की कार्यकुशलता का आंकलन किया जाये।

(3) शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में उच्चतर वेतनमान संस्तुत किये जा रहे हैं, कदाचित यह राज्य को शिक्षा हब (Education Hub) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सके।

(4) शिक्षा विभाग में शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग अलग-अलग गठित किये जाने चाहिए तथा शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रशासनिक संवर्ग में तैनात नहीं किया जाना चाहिए ताकि अनुभवी एवं योग्य अध्यापक अध्यापन कार्य संचालित करते रहें एवं राज्य सेवा से सीधी भर्ती द्वारा आने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य में लगाया जायें। इन दोनों संवर्गों की संवर्गीय नियंत्रण की व्यवस्था अलग-अलग की जानी चाहिए।

(5) संविधान के तिहत्तरवें व चौहत्तरवें संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को निचले स्तर पर पहुंचाया गया है एवं व्यवस्थाओं में जन सहभागिता बढ़ाई गयी है। समिति का मत है कि शिक्षकों के कार्यों के मूल्यांकन हेतु यथा आवश्यक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का सहयोग लिया जाना चाहिए। इस मूल्यांकन में खरे न उतरने वाले शिक्षकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने चाहिए। यदि अशासकीय विद्यालयों का प्रबन्ध तंत्र कार्यवाही न करे तो उनका वित्त पोषण समाप्त किया जाना चाहिए तथा मान्यता भी समाप्त की जानी चाहिए।

3- प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत किये गये वेतनमान के ऐरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। उच्चीकृत वेतनमान के भुगतान की प्रक्रिया समदिनांकित शासनादेश संख्या 25/XXVII (7) /2009 तथा संख्या 27/XXVII (7) /2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 के अनुसार रहेगी।

4- उपरोक्तानुसार उच्चीकृत किये गये वेतनमानों में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या-395/XXVII (7) /2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 एवं समदिनांकित शासनादेश संख्या-25/XXVII (7) /2009 तथा संख्या 27/XXVII (7) /2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 के अनुसार किया जाएगा। लेकिन रु० 8000-13500 के अपुनरीक्षित वेतनमान का दिनांक 1-1-2006 से वेतन बैंड-2 में पुनरीक्षित वेतन बैंड तथा ग्रेड पे का निर्धारण संलग्नक-2 के अनुसार किया जाएगा। यदि संलग्नक-2 में उल्लिखित रु० 8000-13,5000 के अपुनरीक्षित वेतनमान की अनुमन्यता के पदधारकों का वेतन पुनरीक्षण वेतन बैंड-3 में किया गया हो, तब उनका वेतन निर्धारण संलग्नक-2 की फिटमेंट तालिका अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - 4123/XXVII (7) /2010 दिनांक 14 जून 2010 में प्राप्त उनकी राहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या सं. 177(1)/ XXIV-4 /2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

अज्ञा से,
(राधिका झा)
अपर सचिव।